

भूटान से मिलेगी बिहार को बिजली

खुशखबरी

रंग लायी मुख्यमंत्री की पहल, केंद्र सरकार ने बिहार से मांगा प्रस्ताव

■ संवाददाता
पटना

आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल रंग लायी. बिहार को भूटान से बिजली देने पर केंद्र सहमत हो गया है. राज्य सरकार ने भूटान की दो पनबिजली परियोजनाओं-पुनातसांचू व मंगडेचू से 1500 मेगावाट बिजली बिहार को आवंटित करने की मांग की है. नयी दिल्ली में 28 सितंबर को होनेवाली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है. केंद्र द्वारा बुलायी गयी इस बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष शामिल होंगे.

भूटान यात्रा पर गये थे सीएम

2011 में चार से सात मई के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूटान की

- ▶ 28 सितंबर की बैठक में बिहार करेगा 1500 मेगावाट बिजली आवंटन का दावा
- ▶ पुनातसांचू और मंगडेचू पनबिजली परियोजनाओं से मिल सकती है बिजली



यात्रा की थी. अपने चार दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री ने पुनातसांचू व अन्य पनबिजली परियोजनाओं का दौरा किया था. भूटान पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया था कि 2020 तक भूटान में पनबिजली परियोजनाओं से 10 हजार मेगावाट बिजली उत्पादित होगी. तब मुख्यमंत्री ने केंद्र से 1500

मेगावाट बिजली की मांग रखी थी. साथ ही वह भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार अनुमति दे, तो बिहार सरकार भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में निवेश कर सकता है.

प्रदेश में है बिजली की किल्लत

बीते दिनों ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने

एक नजर में

बिहार की जरूरत	3300 मेगावाट
वर्तमान में उपलब्धता	1500-1700 मेगावाट
वर्तमान खपत	122.11 यूनिट प्रति व्यक्ति
राष्ट्रीय खपत	778.71 यूनिट प्रति व्यक्ति

इन परियोजनाओं से मिल रही बिजली

परियोजनाएं	कुल उत्पादन	बिहार का हिस्सा
ताला	1020	260.10 मेगावाट
चूखा	270	80 मेगावाट
तीस्ता	510	108.43 मेगावाट

विद्युत आपूर्ति हो सकती है.

निदेशक मंडल में तीन भारतीय

वैसे भी भूटान की अभी तीन पनबिजली परियोजनाएं ताला, चूखा व तीस्ता से बिहार को केंद्रीय सेक्टर के तहत करीब 440 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो रही है. दोनों परियोजनाएं भारत सरकार के सहयोग से बन रही हैं, जो 2016-17 में पूरा होंगी. गौरतलब है कि परियोजना के निदेशक मंडल में भूटान सरकार के चार व भारत सरकार के तीन अधिकारी हैं.

केंद्र सरकार का पत्र मिला है. बिहार सरकार 1500 मेगावाट की मांग रखेगी. उम्मीद है कि बिहार में बिजली संकट को देखते हुए केंद्र सकाशात्मक रूप से विचार करेगा. **अजय नायक,** प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग